



VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918988885050

+918988886060

www.vajiraoinstitute.com

info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS

(आज का विश्लेषण)

(11 January 2025)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया का दायरा व्यापक हुआ
- 2024 अब तक का सबसे गर्म साल, साथ ही तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की जलवायु सीमा के पार
- डोनाल्ड ट्रम्प को 'बिना शर्त रिहाई' की सजा सुनाई गई
- MCQ

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया का दायरा व्यापक हुआ:

चर्चा में क्यों है?

- परंपरागत रूप से, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) का उत्तराधिकारी अगला सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त होता है। पहली बार, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 के अनुसार, इसके चयन के दायरे को व्यापक बनाया जा सकता है।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। चुनाव आयोग में वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त - ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू शामिल हैं।



'मुख्य चुनाव आयुक्त' की चयन प्रक्रिया का दायरा व्यापक कैसे हुआ?

- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के बाद वरिष्ठतम चुनाव आयुक्त, ज्ञानेश कुमार अभी भी दावेदारी में हो सकते हैं, लेकिन अब नए कानून के अनुसार, विधि मंत्रालय चयन समिति के लिए पांच नामों का

ADDRESS:



एक पैनल तैयार करने के लिए विधि मंत्री की अध्यक्षता में एक खोज समिति का गठन करेगा।

- उसके बाद प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता वाली चयन समिति उन नामों में से से चयन कर सकती है या बाहर से भी "किसी अन्य व्यक्ति" पर विचार कर सकती है।

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें)

अधिनियम, 2023 के प्रमुख प्रावधान:

- इस कानून में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और निष्कासन जैसे पहलू शामिल हैं।
- राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक चयन समिति, जिसमें प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे, की सिफारिश के आधार पर करेंगे।
- कानून मंत्री की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति, चयन समिति को नामों का एक पैनल प्रस्तावित करेगी, जिसमें पात्रता मानदंड के साथ उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के सचिव के समकक्ष पद पर होना आवश्यक होगा।

ADDRESS:



निर्वाचन आयोग में नियुक्तियों को लेकर नया कानून क्यों लाया गया?

- उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद लाया गया है। इसके पीछे की वजह 2015 से 2022 के बीच दायर कई याचिकायें थी, जिसमें चुनाव आयुक्तों को चुनने में केंद्र सरकार की विशेष शक्तियों को चुनौती दी गई थी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय में कहा था कि संविधान के संस्थापकों ने कभी भी निर्वाचन आयोग में नियुक्तियों को लेकर कार्यपालिका को विशेष नियुक्ति शक्तियां देने का इरादा नहीं किया था। निर्वाचन आयोग में नियुक्तियों को पूरी तरह से कार्यपालिका पर छोड़ने के "विनाशकारी प्रभाव" के बारे में चिंतित होकर, सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई प्रक्रिया स्थापित की।
- हालांकि नई प्रक्रिया तब तक लागू रहने वाली थी जब तक संसद नियुक्तियों के लिए कानून नहीं बना देती।
- संसद ने आखिरकार दिसंबर 2023 में एक कानून बनाया, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक शॉर्टलिस्ट पैनल और एक चयन समिति के माध्यम से करना अनिवार्य कर दिया गया। इस अधिनियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति के सदस्य के रूप में हटा दिया गया।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



चुनाव आयोग में नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला:

- सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने 2 मार्च 2023 को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश वाली एक उच्च-शक्ति समिति को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों (ECs) का चुनाव करना चाहिए।

चुनौती क्या दी गयी थी?

- संविधान के अनुच्छेद 324 (2) के अनुसार "चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की संख्या, यदि कोई हो, को राष्ट्रपति समय-समय पर तय कर सकते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी"।
- इस मामले में चुनौती यह थी कि उस समय तक चूंकि इस मुद्दे पर संसद द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया था, इसलिए न्यायालय को "संवैधानिक शून्य" को भरने के लिए कदम उठाना चाहिए।

ADDRESS:



सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया?

- न्यायमूर्ति जोसेफ ने फैसला लिखते हुए कहा कि "मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सलाह पर की जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता (विपक्ष का कोई नेता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे"।
- अदालत ने यह भी कहा, "यह निर्णय संसद द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी कानून के अधीन होगा"। इसका मतलब यह है कि संसद इस मुद्दे पर एक नया कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रभाव को समाप्त भी कर सकती है।

भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI):

- भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत देश में संसद, राज्य विधानसभाओं, राज्य विधान परिषदों, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने और विनियमित करने के लिए की गई थी।
- आयोग में तीन सदस्य हैं, और निर्णय बहुमत से किए जाते हैं।

ADDRESS:



2024 अब तक का सबसे गर्म साल, साथ ही तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की जलवायु सीमा के पार:

परिचय:

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने 10 जनवरी को कहा कि वर्ष 2024, 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के निशान को पार करने वाला पहला वर्ष बन गया है।
- यूरोपीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (ECMWF) द्वारा संचालित कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में पृथ्वी की सतह का वार्षिक औसत तापमान पूर्व-औद्योगिक समय से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक था।
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने ECMWF द्वारा उपयोग किए गए डेटासेट सहित छह डेटासेट का उपयोग करके निष्कर्ष निकाला कि 2024 पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में 1.55 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म था।



ADDRESS:



- उल्लेखनीय है छह डेटासेट में से प्रत्येक ने 2024 को अब तक का सबसे गर्म वर्ष पाया, लेकिन उनमें से सभी ने 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान दर्ज नहीं किया।

1.5 डिग्री सेल्सियस की जलवायु सीमा क्या है?

- उल्लेखनीय है कि तापमान वृद्धि की 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा 2015 के पेरिस समझौते में उल्लिखित एक महत्वपूर्ण सीमा है, जो दुनिया से वैश्विक तापमान में वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से “2 डिग्री सेल्सियस से भी कम” तक सीमित रखने का आह्वान करती है, जबकि इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर रखने के लिए “प्रयास जारी रखने” का आह्वान करती है। पेरिस समझौते में कहा गया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य का पीछा करने से “जलवायु परिवर्तन के जोखिम और प्रभाव काफी कम हो जाएंगे”।

1.5 डिग्री जलवायु सीमा पार करने के बाद क्या होगा?

- हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार 1.5 डिग्री की जलवायु सीमा मनमाने ढंग से तय की गई सीमा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के संदर्भ में, इस सीमा को पार करने के बाद कुछ भी नया नहीं होने वाला है। विज्ञान केवल यही कहता है कि गर्मी बढ़ने के साथ जलवायु प्रभाव अधिक गंभीर और लगातार होने की उम्मीद है।



- ऐसे में वर्ष 2024 के उल्लंघन का मतलब यह नहीं है कि 1.5 डिग्री का लक्ष्य खत्म हो गया है। 2015 के पेरिस समझौते में उल्लिखित यह लक्ष्य, आमतौर पर दो से तीन दशकों में दीर्घकालिक तापमान प्रवृत्तियों को संदर्भित करता है, न कि वार्षिक या मासिक औसत को।
- ECMWF के अनुसार "एक या दो साल में अगर तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि पेरिस समझौते का उल्लंघन हुआ है। हालांकि, वर्तमान में तापमान में वृद्धि की दर प्रति दशक 0.2 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, इसलिए 2030 के दशक के भीतर पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री लक्ष्य का उल्लंघन होने की संभावना बहुत अधिक है"।
- उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष का उल्लंघन कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि WMO पिछले दो वर्षों से कह रहा है कि 2027 से पहले इस सीमा को पार करना लगभग तय है।
- साथ ही वैश्विक उत्सर्जन अभी भी बढ़ रहा है, और 2030 के उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को पूरा न कर पाना लगभग तय है। इसलिए, इस बात की पूरी संभावना है कि 2024 में जो उल्लंघन हुआ है, वह अगले दशक के भीतर एक सामान्य बात बन जाएगा।

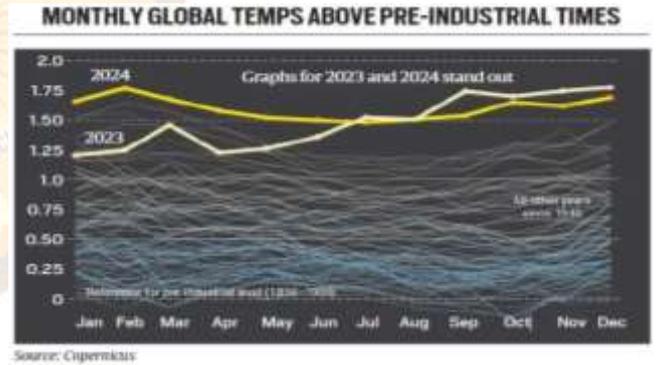


- नतीजतन, यह नया डेटा जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए देशों की ओर से किसी भी नए प्रतिक्रिया उपायों को ट्रिगर करने की संभावना नहीं है, जो अब तक गंभीर रूप से अपर्याप्त रहा है।

2023, 2024 के असाधारण रूप से गर्म होने के क्या कारण रहे हैं?

- वर्ष 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष बन गया है, जो 2023 से आगे निकल गया है जो पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में 1.45 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म था।

- साथ में, ये दोनों वर्ष असाधारण रूप से गर्म रहे, और कई रिकॉर्ड तोड़ने वाले तापमान की घटनाएँ देखी गईं। जुलाई 2023 से लेकर अब तक का हर महीना,



जुलाई 2024 को छोड़कर, पूर्व-औद्योगिक समय के इसी मासिक औसत से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म रहा है।

- ECMWF ने कहा कि पिछले दशक में देखी गई तेजी से बढ़ती गर्मी की प्रवृत्ति में भी वर्ष 2023 और 2024 अलग हैं। उदाहरण के लिए, पिछला सबसे गर्म वर्ष, 2016, जो पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में 1.29 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

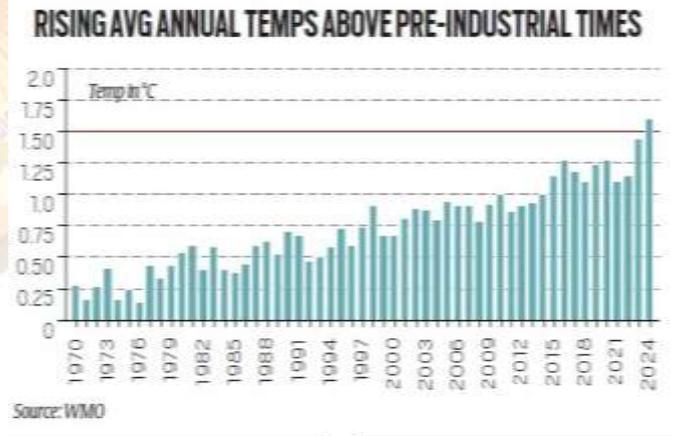


था, एक बहुत मजबूत एल नीनो से प्रभावित था। 2023 और 2024 के दौरान भी अल नीनो का प्रभाव रहा, लेकिन यह 2015-2016 की घटना की तुलना में हल्का था।

- ECMWF ने कहा कि 2023 और 2024 की असामान्य गर्मी कई अन्य कारकों के कारण हो सकती है, हालांकि कोई एक प्रमुख कारण नहीं था।

2024 की असामान्य गर्मी के विभिन्न कारण:

- ECMWF ने कई अन्य महासागर क्षेत्रों में "अभूतपूर्व" अल नीनो जैसी प्रणालियों को संभावित कारणों में से एक बताया।
- जनवरी 2022 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में टोंगा के पास पानी के नीचे



एक ज्वालामुखी विस्फोट और 2024 में शिपिंग उद्योग से कम सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन भी गर्मी में योगदान दे सकता है। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड कुछ सौर विकिरण को परावर्तित करता है, जिससे यह पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता।

ADDRESS:



- असामान्य गर्मी सूर्य के कारण भी हो सकती है, जो अपने नियमित 11-वर्षीय सौर चक्र के दौरान 2024 में अपने सौर अधिकतम चरण में था। ECMWF ने कहा कि सौर अधिकतम चरण के दौरान पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा में वृद्धि ने वार्मिंग में योगदान दिया हो सकता है।
- लेकिन ये केवल संभावनाएं हैं। 2023-24 वार्मिंग के संभावित कारणों का अधिक निश्चित विश्लेषण बाद में आएगा।

2025 और उसके बाद की स्थिति:

- 2023 और 2024 में देखे गए असाधारण रुझान इस साल भी जारी रहने की संभावना नहीं है। अभी तक, 2025 के सबसे गर्म वर्ष के रूप में उभरने की उम्मीद नहीं है। उल्लेखनीय है कि पिछले दशक में, वार्षिक तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में 1.1 और 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है, और इस साल भी इसी सीमा में रहने की उम्मीद है।
- WMO की पिछले साल जारी रिपोर्ट के अनुसार, 2028 से पहले किसी एक वर्ष में वार्षिक औसत तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.9 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होने की संभावना है। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2028 तक पाँच साल के औसत वार्षिक तापमान के 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने की 50% संभावना है।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



डोनाल्ड ट्रम्प को 'बिना शर्त रिहाई' की सजा सुनाई गई:

परिचय:

- राष्ट्रपति-निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्प को न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने 'हस मनी' के जुर्म में "बिना शर्त बरी" करने की सज़ा सुनाई, उन्हें व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के 34 गंभीर अपराधों के लिए बिना जुर्माने, कारावास या परिवीक्षा के रिहा कर दिया।



- लेकिन जब तक व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के लिए दोषसिद्धि को किसी दिन पलट नहीं दिया जाता, तब तक ट्रम्प, के आपराधिक रिकॉर्ड में अपराध दर्ज रहेंगे, जिससे वे आपराधिक मुकदमे, दोषी करार और सजा का सामना करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन जाएंगे।
- हालांकि उन्हें अपराधी घोषित किए जाने के अलावा कोई दंड नहीं भुगतना पड़ेगा, लेकिन यहाँ कुछ संभावित प्रभाव हैं जो नहीं बदलेंगी:

ADDRESS:



क्या वह अब भी मतदान कर सकते हैं?

- फ्लोरिडा में मतदान के लिए पंजीकृत ट्रंप अपनी सज़ा के बावजूद भी मतदान के पात्र बने हुए हैं। फ्लोरिडा में अधिकांश अपराधियों को उनकी सज़ा पूरी होने के बाद मतदान का अधिकार बहाल कर दिया जाता है, सिवाय हत्या या यौन अपराधों के, जिनके लिए क्षमादान की आवश्यकता होती है।
- चूँकि ट्रंप की सज़ा न्यूयॉर्क में हुई थी, जहाँ रिहाई के बाद मतदान का अधिकार बहाल कर दिया जाता है, इसलिए फ्लोरिडा में उनकी पात्रता बरकरार है।

क्या डोनाल्ड ट्रंप दोषी पाए जाने के बाद भी पद पर बने रह सकते हैं?

- संघीय कानून किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर राष्ट्रपति बनने से नहीं रोकता है। राज्य के कानून इस बात पर अलग-अलग हैं कि आपराधिक रिकॉर्ड वाला व्यक्ति राज्य या स्थानीय कार्यालयों के लिए चुनाव लड़ सकता है या नहीं, कुछ के लिए क्षमा या निष्कासन की आवश्यकता होती है।
- हालाँकि, संघीय कार्यालय के लिए ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं है।

क्या इससे उनके लिए व्यावसायिक अवसर खत्म हो जाएंगे?

- ट्रंप की सजा उन्हें शराब के लाइसेंस रखने से रोक सकती है, लेकिन उनके गोल्फ कोर्स और होटल अभी भी शराब परोस सकते हैं क्योंकि उनकी संपत्ति कॉर्पोरेट



संस्थाओं के स्वामित्व में है, और वे सीधे शराब के लाइसेंस रखने में शामिल नहीं हैं।

- सजा उन्हें कैसीनो व्यवसाय में फिर से प्रवेश करने से भी रोक सकती है, क्योंकि अपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति आमतौर पर गेमिंग लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

क्या डोनाल्ड ट्रंप को माफी मिल सकती है?

- केवल न्यूयॉर्क के गवर्नर ही डोनाल्ड ट्रंप को उनकी सजा के लिए माफी दे सकते हैं, क्योंकि इस मामले की सुनवाई राज्य की अदालत में हुई थी। राष्ट्रपति द्वारा माफी केवल संघीय अपराधों पर लागू होती है।
- ऐसा लगता नहीं है कि न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल, एक डेमोक्रेट, ट्रंप को माफी देंगी। पिछले महीने जब उनसे पूछा गया, तो उन्होंने इसकी पुष्टि या खंडन नहीं किया, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि माफी प्रक्रिया के लिए "पश्चाताप" जैसे कारकों की आवश्यकता होती है।
- वहीं डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और मामले को "धोखा" कहा।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



MCQs

1. चर्चा में रहे 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2023' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इस कानून में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और निष्कासन जैसे पहलू शामिल हैं।
2. इसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सलाह पर की जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans:(a)



2. भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को विशेष परिस्थितियों में पूर्ण न्याय के लिए कानून निर्माण की असाधारण शक्ति प्रदान करती है?

(a) अनुच्छेद 124

(b) अनुच्छेद 141

(c) अनुच्छेद 224

(d) अनुच्छेद 270

Ans:(b)

3. चर्चा में रहे '1.5 डिग्री सेल्सियस की जलवायु सीमा' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. तापमान वृद्धि की 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा 2015 के पेरिस समझौते में उल्लिखित एक महत्वपूर्ण सीमा है।

2. पेरिस समझौते में उल्लिखित यह लक्ष्य, आमतौर पर दो से तीन दशकों में दीर्घकालिक तापमान प्रवृत्तियों को संदर्भित करता है, न कि वार्षिक या मासिक औसत को।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans:(c)



4. वर्ष 2023, 2024 के असाधारण रूप से गर्म होने के कारणों को लेकर निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) कई महासागर क्षेत्रों में "अभूतपूर्व" अल नीनो जैसी प्रणालियों की उपस्थिति।
- (b) नियमित 11-वर्षीय सौर चक्र के दौरान 2024 में अपने सौर अधिकतम चरण में।
- (c) 2024 में शिपिंग उद्योग से कम सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन।
- (d) उपर्युक्त सभी सही हैं।

Ans:(d)

5. चर्चा में रहे न्यूयॉर्क के एक कोर्ट द्वारा डोनाल्ड ट्रम्प को 'बिना शर्त रिहाई' की सुनाई गयी सजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इस सजा के तहत उन्हें अपराधी घोषित किए जाने के अलावा कोई दंड नहीं भुगतना पड़ेगा।
2. राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद यह सजा बिना माफ़ी के स्वयं समाप्त हो जाएगी।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

ADDRESS:



VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918988885050
+918988886060



www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com



- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans:(a)



ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)